वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र

द हिन्दू, (16 Feb.)

संदर्भ

- हल ही में रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क (RRA) नामक संस्था ने वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों का एक नया मानचित्र प्रकाशित किया है।
- इस एटलस में न केवल वर्षा पर आधारित खेती वाले क्षेत्रों की कृषि-जैव विविधता, अपितु सामाजिक-आर्थिक दशाओं का भी वर्णन है।
- यह एटलस यह बताने का प्रयास करता है कि नीतिगत पक्षपात के कारण इनमें से कई क्षेत्रों में खेती करना क्यों लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रहा है।

वर्तमान चुनौतियाँ

- भारत के पाँच किसानों में से तीन सिंचाई से नहीं, अपितु वर्षा के पानी से फसलें उपजाते हैं। लेकिन सरकार का प्रति हेक्टेयर निवेश इन भूमियों में सिंचाई भूमियों की तुलना में 20 गुना कम है।
- सरकार जो फसलें खरीदती है वह मुख्य रूप से बड़े-बड़े सिंचित भूमियों से आती हैं। सरकार की मूर्धन्य कृषि योजनाएँ अधिकांशत: ऐसे बनाई गई हैं जिससे वर्षा पर निर्भर खेतों को कोई लाभ नहीं पहुँचता।
- वर्षा-आधारित क्षेत्रों के प्रति "लापरवाही" हुई है जो इन क्षेत्रों में किसानों के लिए कम आय का कारण बन रहा है। वर्षा पर निर्भर किसान खेती से जो आय पाते हैं वह सिंचित खेतों के किसानों के आय की तुलना में 40% कम है।
- बड़े बांधों और नहर नेटवर्क के माध्यम से सिंचित भूमि को प्रति हेक्टेयर 5 लाख का निवेश मिलता है। वर्षा आधारित भूमि में वाटरशेड प्रबंधन का खर्च केवल 18,000-25,000 है।
- उपज का अंतर निवेश के अंतर के अनुपात में नहीं है। जब खरीद की बात आती है, तो 2001-02 और 2011-12 के बीच के दशक में सरकार ने गेहूं और चावल पर 5.4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए।
- दूसरी ओर वर्षा-निर्भर क्षेत्रों में उगाये जाने वाले मोटे अनाजों की उसी अवधि में जो खरीद हुई वह मात्र 3,200 करोड़ रु. थी।
- फ्लैगशिप सरकारी योजनाएं, जैसे कि बीज और उर्वरक सब्सिडी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचित क्षेत्रों के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- वर्षा-निर्भर किसानों के लिए इन योजनाओं को विस्तारित तो किया गया है परन्तु उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना।

आगे की राह

- वर्षा-निर्भर किसानों तक सिंचित भूमि के किसानों के समान शोध एवं तकनीक पहुँचाने और उत्पादन में सहयोग करने के विषय में सरकार को एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- सच पूछा जाए तो बहुत अधिक खरीद से अच्छा यह होगा कि दीर्घकाल में वर्षा पर निर्भर रहने वाले किसानों को नकद उत्प्रेरण और आय समर्थन, जैसे – PM किसान योजना का लाभ दिया जाए।

स्त्री सुरक्षा के लिए तीन बड़ी पहलें

Pib, (18 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्त्री सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, SCIM पोर्टल (सेफ सिटी प्रोजेक्ट), राज्यों में DNA विश्लेषण की सुविधाएँ जैसी तीन बड़ी पहलों की शुरुआत की हैं।
- **पैनिक बटन** :- संकट के समय कोई भी स्त्री इस बटन का उपयोग कर सकती है। इसके लिए उसे ये कदम उठाने होंगे।

- यदि स्मार्ट फोन है तो पॉवर बटन को तीन बार तेजी से दबाना होगा। किसी भी फोन से 112 पर कॉल करना।
- यदि फीचर फोन है तो 5 और 9 अंकों को देर तक दबाना। 112 इंडिया मोबाइल एप्प का प्रयोग करना।

- **SCIM पोर्टल (सेफ सिटी प्रोजेक्ट) :-** यह योजना आठ शहरों में चलाई जा रही है। प्रत्येक शहर में ऐसे स्थलों का पता लगाना जो संवेदनशील हैं। ऐसे स्थलों पर CCTV लगाना। अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में स्वचालित नम्बर प्लेट पढ़ने की मशीन लगाना। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के बाहर जो संकटग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ भारी गश्ती करना। सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था सुधारना। स्त्रियों के लिए सार्वजनिक शौचालय की सुविधा बढ़ाना। थाने में महिला सहायता डेस्क स्थापित करना।

राज्यों में DNA विश्लेषण की सुविधाएँ

- यौन अपराधों के निपटारे में होने वाली देर को ध्यान में रखते हुए DNA नमूनों की जाँच आवश्यक हो जाती है।
- अभी DNA विश्लेषण की सुविधा कुछ ही शहरों में है। अब इसके लिए नई प्रयोगशालाएँ चेन्नई, मदुरै, आगरा, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता में बनाई जाएँगी।

सर्वेक्षण और रिपोर्ट : एम्स

Pib, (18 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साहचर्य में एक सर्वेक्षण किया था।
- जिसमें 36 राज्यों और संघीय क्षेत्रों में रहने वाले 2 लाख घरों एवं 4.73 लाख लोगों से 186 जिलों में जानकारी ली गई थी। ये सभी लोग 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु के थे।

मुख्य बिंदु

- भारत में छह करोड़ शराब की लत वाले व्यक्ति रहते हैं। यह संख्या 172 देशों की जनसंख्या से भी अधिक है।
- 1 करोड़ से अधिक भारतीय (2.8%) गाँजा, भाँग, चरस, हेरोइन और अफीम का प्रयोग करते हैं।
- नशे की लत में पड़े 20 लोगों में से मात्र एक का अस्पताल में इलाज होता है।
- देश में पी जाने वाली 30% शराब देशी शराब होती है।
- पंजाब और सिक्किम में गांजे से होने वाली बीमारियाँ राष्ट्रीय औसत से तिगुनी होती हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला नशीला पदार्थ हेरोइन है और उसके बाद ओपीओइड और अफीम का स्थान आता है।

- 1% से कम अर्थात् 18 करोड़ लोग दर्दनिवारक का प्रयोग करते हैं। चिंता की बात यह है कि इनका प्रचलन बच्चों और किशोरों में अधिक है।
- देश में जिन नशीले द्रव्यों का प्रचलन सबसे कम है, वे हैं – कोकेन (0.10%), एम्फेटमिन (18%) और हेल्यूसिनोजन (0.12%)।

सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये कार्य

- नशीले द्रव्यों की तस्करी की समस्या से निबटने के लिए सरकार ने कई नीतिगत और अन्य पहलें की हैं।
- नवम्बर 2016 में सरकार ने नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की स्थापना की थी और नार्कोटिक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की योजना को पुनर्जीवित किया था।
- 2017 में सरकार ने विभिन्न अवैध औषधियों के पकड़े जाने पर दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि बढ़ा दी थी।
- संसार के अन्य देशों के साथ कारगर समन्वयन के लिए भारत ने 37 द्विपक्षीय समझौते किये हैं।
- नार्कोटिक नियंत्रण ब्यूरो को नए सॉफ्टवेर बनाने के लिए धनराशि दी गई है। उदाहरण के लिए एक जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली बनी है जिस पर अवैध औषधियों से सम्बंधित अपराध और अपराधियों का डाटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
- सरकार ने राष्ट्रीय औषधि दुरूपयोग नियंत्रण कोष भी गठित किया है जिससे नार्कोटिक औषधियों के अवैध व्यापार की रोकथाम

करने, नशे की लत के लोगों को फिर से बसाने, जनसामान्य को इस विषय में जागरूक करने आदि कामों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशीले द्रव्यों की माँग को घटाने के लिए राष्ट्रीय कार्योजना (2018-2023) का प्रारूप बनाया है जिसमें नशीले द्रव्यों और औषधियों के दुरूपयोग की समस्या पर कार्रवाई करने के उपाय बताये गये हैं।

केन्द्रीय वक्फ परिषद्

Pib, (18 Feb.)

संदर्भ

- केन्द्रीय वक्फ परिषद् एक वैधानिक निकाय है, जो 1964 में भारत सरकार द्वारा वक्फ एक्ट, 1954 (अब वक्फ एक्ट, 1995 का एक उपभाग) के तहत स्थापित किया गया था।
- यह राज्य वक्फ बोर्डों के काम से संबंधित मामलों पर केंद्र को सलाह देने और देश में वक्फ के उचित प्रशासन के लिए स्थापित किया गया है।
- मुस्लिम कानून के तहत परोपकारी मुस्लिम चल-अचल संपत्तियों को धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए स्थाई रूप से दान दे देते हैं।

Central Waqf Council
Ministry Of Minority Affairs, Government Of India

रचना और नियुक्तियाँ

- परिषद की अध्यक्षता एक अध्यक्ष करते हैं, जो वक्फ के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री होते हैं और इसमें अधिकतम 20 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम के अंतर्गत दिए गये प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाता है।

भारत में अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति

- आजादी के बाद देश के पिछड़े क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों, विशेषकर लड़कियों की शैक्षिक अधिकारिता तथा रोजगारपरक कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं।
- यह वर्ग स्वतंत्रता के बाद से ही इन सुविधाओं से वंचित रहा है।
- हाल के दिनों में इन वर्गों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया है, ताकि देश के 308 जिलों में अल्पसंख्यकों, विशेषकर लड़कियों की सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक अधिकारिता और रोजगारपरक कौशल विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्यक्रमों का देश के 308 जिलों तक विस्तार किया।

विजन जीरो सम्मेलन

द हिन्दू, (18 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि शून्य सम्मेलन अर्थात विजन जीरो सम्मलेन आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य व्यवसायगत सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- यह सम्मेलन एक ऐसा मंच है, जो विचारों, प्रथाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है।
- इस सम्मलेन का आयोजन श्रम एवं नियोजन मंत्रालय और जर्मनी के सामाजिक दुर्घटना बीमा प्रतिष्ठान के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है और इसमें सम्मिलित होने वाले अन्य संस्थान हैं – IIT बॉम्बे, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ।

VISION ZERO
nyc.gov/visionzero

क्या है?

- दृष्टि शून्य अवधारणा चार आधारभूत सिद्धांतों पर टिकी हुई है, यथा – जीवन से समझौता नहीं हो सकता, मानव से गलती हो जाती है, सहन की क्षमता मानवीय प्रतिरोध पर निर्भर होती है तथा लोगों को सुरक्षित यातायात और सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार है।

- इस अवधारणा के तहत ये कार्य करने आवश्यक होते हैं – जोखिमों को नियंत्रित करना, मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थलों को सुरक्षा एवं स्वास्थ्यकर बनाना तथा कार्यबल के कौशल में उत्क्रमण करना।

अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक नई कंपनी

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (19 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक नई कंपनी की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाइयों द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास कार्य का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

सत्यमेव जयते

इसरो isro

प्रमुख विशेषताएं

- उद्योग के लिए लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना, जिसमें नई कंपनी अंतरिक्ष विभाग/ इसरो से लाइसेंस तथा उद्योगों के लिए उप-लाइसेंस प्राप्त करेगी।
- निजी क्षेत्र के सहयोग से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV) का निर्माण करना।
- उद्योग के माध्यम से पोलर एसएलवी का उत्पादन करना।
- प्रक्षेपण तथा इस्तेमाल सहित अंतरिक्ष – आधारित उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन तथा विपणन।
- इसरो केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाइयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना।

महत्त्व

- कैबिनेट के इस फैसले से निश्चित रूप से निजी क्षेत्र को लांचरों और उपग्रहों के उत्पादन में अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
- इसरो उपग्रह प्रक्षेपकों के निर्माण में निजी क्षेत्र से सहायता प्राप्त कर रहा है ताकि वह अनुसंधान एवं विकास कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019

लाइव मिंट, (19 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (एनपीई 2019) को अपनी स्वीकृति दे दी है।

उद्देश्य

- इस नीति में चिपसेटों सहित महत्त्वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमताओं को प्रोत्साहित कर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बना कर भारत को 'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम)' के एक वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

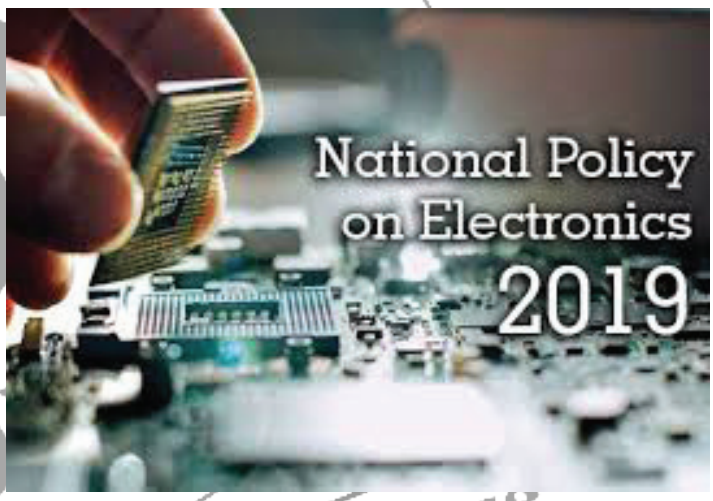

मुख्य बिंदु

- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ईएसडीएम सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा।
- ईएसडीएम की समूची मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जो के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2012 (एनपीई 2012) के तत्वावधान में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से एक प्रतिस्पर्धी भारतीय ईएसडीएम वैल्यू चेन से जुड़ी नींव सफलतापूर्वक मजबूत हो गई है।
- एनपीई 2019 में इस नींव को और मजबूत करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि देश में ईएसडीएम उद्योग के विकास की गति तेज की जा सके।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (एनपीई 2019) ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2012 (एनपीई 2012) का स्थान लिया है।

Committed to Excellence

कार्यान्वयन

- रणनीति एवं लक्ष्य कार्यान्वयन रणनीति: इस नीति से इसमें परिकल्पित रोडमैप के अनुसार ही देश में ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए अनेक योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं एवं उपायों को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

लक्ष्य

- वर्ष 2025 तक 400 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 26,00,000 करोड़ रुपये) का कारोबार हासिल करने हेतु आर्थिक विकास के लिए ईएसडीएम की समूची वैल्यू चेन में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना।

प्रभाव

- एनपीई 2019 को कार्यान्वित करने पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से देश में ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिए अनेक योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं इत्यादि को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- इससे भारत में निवेश एवं प्रौद्योगिकी का प्रवाह सुनिश्चित होगा, जिससे देश में ही निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के ज्यादा मूल्य वर्धन और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के अधिक उत्पादन के साथ-साथ उनके निर्यात का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
- इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क नामक संस्था द्वारा इस क्षेत्र के लिए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया गया है।
2. इस मानचित्र में न केवल वर्षा पर आधारित खेती वाले कृषि क्षेत्रों की कृषि-जैव विविधता, अपितु सामाजिक-आर्थिक दशाओं का भी वर्णन है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम (SCIM) पोर्टल की शुरूआत की गई है।
2. स्कीम पोर्टल आठ राज्यों में चलाई जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में एम्स द्वारा किये गये सर्वेक्षण के रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला नशीला पदार्थ हेरोइन है।
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशीले द्रव्यों की माँग को घटाने के लिए राष्ट्रीय कार्योजना 2018 से 2023 का प्रारूप बनाया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

4. 'केन्द्रीय वक्फ परिषद्' के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?

(a) यह एक गैर-वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई।
(b) इसके एक अध्यक्ष नियुक्त होते है, जो केन्द्रीय मंत्री होते है।
(c) इसमें अध्यक्ष के अलावा बीस सदस्य होते है।
(b) यह राज्य वक्फ बोर्डों के काम से संबंधित मामलों पर केन्द्र को परामर्श देने के लिए स्थापित किया गया है।

5. 'विजन जीरो सम्मेलन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है।
2. इस सम्मेलन का आयोजन श्रम एवं नियोजन मंत्रालय और जर्मनी के सामाजिक दुर्घटना बीमा प्रतिष्ठान के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक नई कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी है।

GS World
Committed To Excellence

2. इस नई कम्पनी से इसरों के केन्द्रो तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाईयों द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास कार्य का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

7. 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2012 का स्थान लेगी।
2. इस नीति के तहत 'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को एक वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

नोट : 14-15 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(d), 4(a), 5(c), 6(d), 7(a), 8(a), 9(c), 10(b), 11(a) होगा।

GS World
Committed To Excellence